[डा. सत्यनारायण जटिया]

की रिस्पांसिबिलिटी का काम कर रही है। परंतु यह स्ट्रक्चर इतना ढीला-ढाला है कि इस में कुछ संस्थाएं तो सहयोग कर रही हैं, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि इसको सुनिश्चित करने के लिए आपने जो निर्देश दिए हैं, उनका पालन ठीक प्रकार से हो, इसके लिए आप क्या उपाय करने वाले हैं?

श्री अनंत गीतेः सर, डीपीई के द्वारा हर छह महीने मेंहम सार्वजनिक उद्यम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मॉनिटरिंग करते हुए, 2014-15 की जो फिगर हमारे सामने आई है, उसमें देश भर के जो 129 सार्वजनिक लोक उद्यम हैं, उन पर सीएसआर को 3,558 करोड़ रुपये खर्च पड़ा, जो इसके नेट प्रॉफिट, 2 परसेंट से आता है। इन 14-15 साल में जो खर्च हुआ है, वह 2,447 रुपये है। वैसे यह अमाउंट sizable है। इस तरह सीएसआर के माध्यम से हम सामाजिक दायित्व की जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और इसी दिशा में हम मंत्रालय द्वारा निरंतर यह प्रयास और यह कोशिश करते आए हैं कि चाहे निजी सेक्टर हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, सीएसआर का सदुपयोग हो सके ।

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, my question is, actually the whole concept of CSR was brought by the Department of Public Enterprises only. Subsequently, it was extended to the private companies by an enactment in the Companies Act. Now, being a pioneer of it, after the enactment of the Companies Act, 2014-15 is the year where you have to check the implementation of law in respect of private companies, the heavy industries' private companies. You are already doing in the public sector. Now, we are almost in the year 2016-17. Your report gives details from 2014-15, the counting year for checking or enforcement of CSR provisions under the Companies Act. I would like to know from the hon. Minister how CSR provisions are being enforced in the private sector companies, how much they have done and how many are defaulters.

श्री अनंत गीतेः सभापति जी, जहां तक सार्वजनिक लोक उद्यम का सवाल है, CPSUs का सवाल है, उसकी जिम्मेवारी निश्चित रूप से लोक उद्यम विभाग की है। जो निजी इंडस्ट्रीज़ हैं, निजी कम्पनीज़ हैं, ये सारी कम्पनीज़ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आती हैं। ...(**व्यवधान**)... मैंने वही जानकारी आपको दी है कि ये कॉरपोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आती हैं। जहां तक मेरे मंत्रालय का सवाल है, लोक उद्यम विभाग का सवाल है, हम उनकी जानकारी रखते हैं और केवल जानकारी ही नहीं रखते, यदि CSR में कोई दुरुपयोग होता है, तो इस संदर्भ में सुझाव भी दिए जाते हैं।

नई शिक्षा नीति संबंधी सुझाव

*140. **श्री महेंद्र सिंह माहराः** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या शिक्षा नीति में परिवर्तन करने के लिए सुझाव प्राप्त करने हेतु देश के विभिन्न राज्यों के मंत्रियों, सचिवों और शिक्षाविदों के साथ मंत्रालय की बैठकें सम्पन्न हो चुकी हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठकें किन-किन स्थानों पर और संस्थानों में आयोजित की गई थीं; और

(ग) क्या राज्यों से प्राप्त सुझावों में शिक्षा नीति में परिवर्तन किये जाने को स्पष्ट किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति (एनईपी) तैयार करने के लिए लगभग एक वर्ष तक अभूतपूर्व सहयोगात्मक, बहु-हितधारक और बहु-आयामी परामर्श प्रक्रिया चलाई है। इस त्रि-आयामी परामर्श प्रक्रिया में ऑनलाइन, जमीनी और राष्ट्रीय स्तर पर विषयगत विचार-विर्मश शामिल था।

यह ऑनलाइन परामर्श प्रक्रिया 26 जनवरी से 31 अक्टूबर, 2015 तक *www.MyGov.in* पोर्टल पर चली थी और 33 अभिचिन्हित प्रकरणों के संबंध में लगभग 29,000 सुझाव प्राप्त हुए हैं। मई से अक्टूबर, 2015 के बीच सभी ग्राम पंचायतों, ब्लॉक, शहरी स्थानीय निकायों, जिलों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में एक व्यापक समयबद्ध, सहभागितापूर्ण, जमीनी स्तार पर परामर्श प्रक्रिया चलाई गई थी और दिनांक 29.02.2016 की स्थिति के अनुसार, स्कूल शिक्षा के संबंध में 1,10,623 ग्रामों, 3250 ब्लॉकों, 725 शहरी स्थानीय निकायों, 340 जिलों और 18 राज्यों ने उच्च शिक्षा के संबंध में और 2738 ब्लॉकों, 962 शहरी स्थानीय निकायों, 406 जिलों तथा 19 राज्यों ने अपने सुझाव *http://survey.mygov.in* पर अपलोड कर दिए हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्री ने नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए परामर्श प्रक्रिया पर विचार-विमर्श करने और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों और विभागों के सुझाव आमंत्रित करने के लिए दिनांक 14.02.2015 को एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की थी। कुल मिलाकर, भारत सरकार के 15 मंत्रालयों ने अपने सुझाव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेज दिए हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्री ने 21 मार्च, 2015 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में, शिक्षा मंत्रियों, सचिवों और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी, जिसमें *MyGov.in* पर सिफारिशों को अपलोड करने की प्रक्रिया सहित परामर्श प्रक्रिया विस्तृत रूप से स्पष्ट की गई थी और प्रक्रिया के साथ-साथ प्रकरणों के संबंध में राज्यों से सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जुलाई-अक्टूबर, 2015 के दौरान विशेषज्ञों, शिक्षाविदों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, नागरिक समाज आदि सहित सभी प्रासंगिक हितधारकों को आमंत्रित करते हुए यूजीसी, एआईसीटीई, एनसीटीई, एआईयू, एनसीईआरटी, सीबीएसई, आईआईएएस, एनएलएमए, एनएएसी, नूपा, इग्नू और केंद्रीय विश्वविद्यालयों जैसे शीर्ष संस्थानों के माध्यम से प्रकरणगत विचार-विमर्श आयोजित किया था। यह भी उल्लेखनीय है कि एनसीईआरटी, सीबीएसई, एनसीटीई और इग्नू ने पैन इंडिया परामर्श किए थे पूरे भारत में परामर्श प्रक्रिया आयोजित की थी। इसके अतिरिक्त मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रकरणगत परामर्श किए जिनमें विषय-विशेषज्ञता वाले विशेषज्ञों के साथ-साथ हितधारकों को विचार-विमर्श के लिए आमंत्रित किया गया था।

विषय के अग्रणी विशेषज्ञों के साथ छह ऑनलाईन वार्तालाप आयोजित किए गए, यूएन सोल्यूशन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म (70 संख्या 0) के माध्यम से फील्ड प्रैक्टिशनर्स को नियुक्त किया

गया, सीबीएसई द्वारा ऑनलाइन सर्वेक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें 15000 उत्तर प्राप्त हुए, सर्वसाधारण को शामिल करने के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र में यूनेस्को के प्रथम श्रेणी के संस्थान, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर एजूकेशन फॉर पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट द्वारा 6017 युवाओं को शामिल करके युवा सर्वेक्षण और फोकस्ड सामूहिक विचार-विमर्श भी आयोजित किया गया था। इसके अतिरिक्त कई संगठनों ने डाक और ई-मेल के माध्यम से अपनी राय सुझाव और इनपुट भेजे हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्री ने जुलाई, 2015 में राज्य सभा और लोक सभा के सभी माननीय सदस्यों को लिखा है जिसमें नई शिक्षा नीति के संबंध में उनके सुझाव और सुविचारित राय आमंत्रित की गई थी।

केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की दिनांक 19 अगस्त, 2015 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित बैठक की कार्यसूची में एक विषय परामर्श प्रक्रिया था। परामर्श प्रक्रिया और प्रकरणों के संबंध में सभी राज्यों और केब के सदस्यों की राय मांगी गई थी। मानव संसाधन विकास मंत्री ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करके सितम्बर-अक्टूबर, 2015 में पूर्व, मध्य, पूर्वोत्तर, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्रों में छह क्षेत्रीय बैठकें आयोजित की थीं जिनमें संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा मंत्रियों और अधिकारियों ने भाग लिया था। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सुझावों सहित अपने निष्कर्ष दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हैं।

भारत सरकार ने 'नई शिक्षा नीति को तैयार करने हेतु समिति' गठित की है। समिति में अध्यक्ष के रूप में श्री टी.एस.आर. सुब्रह्मण्यन, पूर्व मंत्रिमंडल सचिव और सदस्यों के रूप में श्रीमती शैलजा चंद्रा, पूर्व मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, श्री सेवाराम शर्मा, पूर्व गृह सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, श्री सुधीर मांकड़, पूर्व मुख्य सचिव, गुजरात और प्रोफेसर जे. एस. राजपूत, पूर्व निदेशक, एनसीईआरटी शामिल हैं। बहु-हितधारकों से प्राप्त सुझाव समिति के पास भेज दिए गए हैं। समिति को अधिदेश दिया गया है कि वह प्राप्त परिणाम दस्तावेज, सिफारिशों और सुझावों की जांच करेगी तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति मसौदे के साथ ही कार्रवाई के लिए फ्रेमवर्क (एफएफए) तैयार करेगी।

Suggestions for new education policy

†*140. SHRI MAHENDRA SINGH MAHRA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether the Ministry has concluded its meetings with the ministers, secretaries and educationists of various States of the country to get suggestions for change in the education policy;

(b) if so, the names of places and institutes where these meetings were held; and

(c) whether the suggestions received from the States indicate a change in the education policy?

† Original notice of the question was received in Hindi.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) The Government of India carried out an unprecedented collaborative, multi-stakeholder and multi-pronged consultation process over nearly a year, for formulating the New Education Policy (NEP). The three-pronged consultation process included online, grassroots and national level thematic deliberations.

The online consultation process was undertaken on *www.MyGov.in* portal from 26th January, 2015 to 31st October, 2015 and nearly 29,000 suggestions have been received on the 33 identified themes. An extensive, time-bound, participative, bottom-up consultative process across Gram Panchayats, Blocks, Urban Local Bodies, districts and States/Union Territories was carried out between May to October, 2015 and as on 29.02.2016, in respect of School Education 1,10,623 villages, 3250 Blocks, 725 ULBs, 340 districts and 18 States and in respect of Higher Education 2738 Blocks, 962 ULBs, 406 districts and 19 States have uploaded their suggestions on *https://survey.mygov.in*

A High Level meeting was taken by Minister for Human Resource Development on 14.02.2015 to discuss the consultative process for formulation of New Education Policy and invite suggestions of other Government of India Ministries and Departments. In all, 15 GoI Ministries have sent their suggestions to MHRD.

A meeting was held by the Minister of Human Resource Development on 21st March, 2015 at Vigyan Bhawan, New Delhi with Education Ministers, Secretaries and other senior officials of the State Governments in which the consultation process, including the process of uploading the recommendations on *MyGov.in,* was explained in detail and suggestions of States on the process as well as the themes were also invited.

MHRD held thematic consultations through Apex level institutions and regulators, such as, UGC, AICTE, NCTE, AIU, NCERT, CBSE, IIAS, NLMA, NAAC, NUEPA, IGNOU and Central Universities by inviting all relevant stakeholders including experts, academics, industry representatives, civil society etc. during July-October, 2015. It may be mentioned that NCERT, CBSE, NCTE and IGNOU held Pan – India consultations. Further, the Ministry held thematic consultations at the national level, in which experts having domain expertise as well stakeholders were invited for deliberations.

Six online talks with leading subject experts, field practitioners engagement through the UN Solutions Exchange Platform (70 nos.), online survey by CBSE with over 15000 responses, youth survey and focus group discussions covering 6017 youth by Mahatma Gandhi Institute for Education for Peace and Sustainable Development, UNESCO Category-I Institute in Asia Pacific were conducted as part of the public

engagement. In addition, several organizations and individuals have sent in their views, suggestions, inputs through post and e-mails.

Minister for Human Resource Development wrote to all Hon'ble Members of Rajya Sabha and Lok Sabha in July 2015 inviting their suggestions and considered views on the New Education Policy.

The consultation process was one of the agenda points in the meeting of Central Advisory Board on Education (CABE) held on 19th August 2015 at Vigyan Bhawan, New Delhi. Views of all States and members of CABE were invited on the consultation process and the themes. Six Zonal Meetings were held by the Minister of Human Resource Development in Eastern, Central, North-Eastern, Western, Southern and Northern Zones covering all States and UTs in September-October 2015 which was attended by Education Ministers and officials of the respective States/UTs. States have submitted their outcome documents with suggestions.

The Government of India has constituted a 'Committee for Evolution of the New Education Policy' for drafting the New Education Policy (NEP). The Committee consists of Shri T.S.R. Subramanian, former Cabinet Secretary as the Chairman and Shrimati Shailaja Chandra, former Chief Secretary, NCT of Delhi, Shri Sevaram Sharma, former Home Secretary, NCT of Delhi, Shri Sudhir Mankad, former Chief Secretary, Gujarat and Prof. J.S. Rajput, former Director, NCERT as members of the Committee. All the suggestions received from multiple stakeholders have been forwarded to the Committee. The Committee is mandated to examine the outcome documents, recommendations and suggestions received and formulate a draft National Education Policy as well as a Framework for Action (FFA).

श्री महेंद्र सिंह माहराः चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि श्री सुब्रह्मण्यम के नेतृत्व में बनी समिति में जो पांच सदस्य हैं, क्या उनमें एससी, एसटी व अल्पसंख्यक वर्ग का भी प्रतिनिधित्व है?

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, I would like to bring to the notice of the hon. Member, when a Committee for evolution of Education Policy was constituted, issues looked at hand were administrative experience of the Committee Members not only in the Centre or the States but also in the area of the NCERT. The Committee was thus constituted. In fact, one of the Members of the Committee — with an apology to her, I am making a declaration here — Shrimati Shailaja Chandraji asked me, 'Please appoint me, because I have been an able administrator. Do not look at me from the context of gender.' So, my request is: This Committee, after exhaustive deliberations, has ensured to include members of all communities across all States. In fact, we particularly engaged even with Ministries across the Government of India and we have received information with regard to what the Education Policy should contain from the Ministries of Social Justice and Empowerment, Youth Affairs and

also Tribal Affairs Ministry. Hence, to say that any community would have been excluded from deliberations is not factually correct.

श्री महेंद्र सिंह माहराः नयी शिक्षा नीति कब तक लागू की जाएगी?

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, I am awaiting a draft from the Committee. Post receipt of draft, it is my intention to call upon every education Minister and Education Secretary of the States, deliberate with them the draft that has been submitted, follow proper constitutional guidelines to ensure this engagement and also discuss with my Cabinet colleagues. After exhaustive deliberations on the draft submitted by the Committee, I can give a timeline with regard to when policy will roll out.

श्री भूपिंदर सिंहः सर, बात यह है कि एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बार-बार यहां चर्चा हुई है। आप जो युनिफार्म एजुकेशन पॉलिसी बनाने जा रही हैं, उसके अन्दर क्या आप इसके बारे में ज्यादा गुरुत्व देंगी कि नेशनल इंटिग्रेशन, नेश्नलिज्म और patriotism के बारे में सिलेबस में बच्चों को सबसे ज्यादा शिक्षा दी जाए? उसके लिए 'पहले मैं इंडियन हूँ' का भाव हो, इसके बारे में क्या जात-पात और धर्म से ऊपर उठ कर कोई ऐसा सिलेबस बनेगा? जो नयी पॉलिसी बनेगी, उसके ऊपर कुछ सुझाव आपके पास आए हैं, अभी तक डेढ़ लाख सुझाव आए हैं, तो क्या उनमें ज्यादातर ऐसे सुझाव हैं और क्या आप उनके ऊपर गौर करने जा रही हैं?

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: I would like to extend my appreciation for the concern that is being expressed by the senior colleague with respect to this question. Yes, we have received suggestions from across the nation on patriotism and nationalism as the forefront. But, I would also like to say here that to address the National Education Policy, the nomenclature of Uniform Education Policy will do a great disservice to the diversity of culture, heritage and language that we have across the States. I, particularly, also like to recognize that there are many MPs that I had written to in both the Houses of Parliament. Eleven have written back to me with their views. Two hon. Members I can mention. Today, in fact, I thank personally Dr. Karan Singh and Shri P.L. Punia, who was here; he also, in his communication to my Ministry has stated that they would like to see that there is no disparity between communities and classes in terms of the education that is given.

SHRI TIRUCHI SIVA: Sir, thank you. I would like to know from the hon. Minister whether any terms of reference are given to the Committees. The recent statistics show that out of the passed out engineering graduates, only 26 per cent are employable. So, instead of producing just graduates, I would like to know from the Ministry whether the new National Education Policy will aim at producing candidates who are employable. Will it aim at that? Do you fix any terms of reference to the Committee?

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, the Committee has been requested to ensure that apart from drafting a policy, to also gives us a framework of action, like I have said before that this framework of action and the roll out of the same will be worked upon and implemented in conjunction with the State Governments. But,

absolutely, it is true that I, as a Minister, also am concerned about not only education but also of the fact that there are institutions to enable employment opportunities for the graduates that come out of our institutions irrespective of them being from engineering institutions or from institutions that impart education in the social science sector. I am sure that the Committee, given that apart from the exhaustive deliberations that has happened across the nation, I am given to believe that it has conducted over 120 meetings including regional workshops based on all the information given to them. Particularly I would like to thank here that over 1,687 urban local bodies and 5,990 blocks had given us their suggestions apart from the fact that 1,10,623 villages have given their written suggestions to us as to what they aspire this policy to have. Employability is very much one of the factors.

श्री गुलाम रसूल बलियावीः शुक्रिया सर, जिस हिसाब से माननीया मंत्री जी ने अपनी बात बताई, इस वक्त जो पूरे मुल्क में खास तौर से एजुकेशन से और समितियों के ताल्लुक से जो माननीय सदस्य ने सवाल किया, सुब्रह्मण्यम जी से रिलेटिड, उसमें बहुत सीधा सा सवाल था कि उसमें अल्पसंख्यक और आपके पिछड़े-ओ.बी.सी. के लोग हैं कि नहीं? तो मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारा जो मौजूदा सैटअप है एजुकेशन का और कमेटियों के गठन का, कहीं ऐसा तो नहीं इन दो बड़े सैक्टर को सिंस-आउट करने की कोई नीति है और अगर नहीं है तो आखिर इनमें क्या कसूर है कि इनको नहीं लाया जाता?

† **جناب غلام رسول بلیاوی:** شکریہ سر، جس حساب سے مانّیہ منتری جی نے اپنی بات بتائی، اس وقت جو پورے ملک میں خاص طور سے ایجوکیشن سے اور سمیتیوں کے تعلق سے جو مانّنے سدسنے نے سوال کیا، سبرامنیم جی سے متعلق، اس میں بہت سیدھا سا سوال تھا کہ اس میں اقلیتوں اور آپ کے پچھڑے، او۔بی۔سی۔ کے لوگ ہیں کہ نہیں؟ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو موجودہ سیٹ-اپ ہے ایجوکیشن کا اور کمیٹیوں کو گٹھن کا، کہیں ایسا تو نہیں ان دو بڑے سیکٹر کو سنس-آؤٹ کرنے کی کوئی نیتی ہے اور اگر نہیں ہے تو آخر ان میں کیا قصور ہے کہ ان کو نہیں لایا جاتا؟

SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, I would like to very humbly appeal to the hon. Member that I don't want to invoke my own sermon to show how micro-minorities are also a part of deliberations. I will only say that, including the Minister seated right before me, the Ministry of Minority Affairs was also very much a part of the deliberations that were undertaken. I can particularly give public thanks to Anjuman-e-Islam Educational Institution from Mumbai that also deliberated on issues with respect to education. Let me reiterate, Sir, that every community, every social segment was taken into consideration and, now, because the Government has given it to able administrators to give us a framework for action on a described policy, we are awaiting a response from them in terms of a policy draft.

† Transliteration in Urdu script.